



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 1983/भाद्रपद 19, 1985

No. 132]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 1983/SRAVANA 19, 1985

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1983

विषय :—विदेशी ऋण/क्रेडिट/अनुदान के मद्दे सीधे ही भुगतान करने की क्रियाविधि के अन्तर्गत किए गए आयातों के संबंध में आयातकों से ब्याज की वसूली—ब्याज की दर में संशोधन ।

मिनिस्टर सं. आई. पी. सी./23/9/83 :—विदेशी ऋण/क्रेडिट/अनुदान के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए लागू लाइसेंस शर्तों में इस बारे में एक विशिष्ट धारा यह भी है कि ऐसे मामलों में जहां सीधे भुगतान/बचन बढ़ता की क्रियाविधि का अनुपालन किया जाता है और आयातित माल और सेवाओं की कीमत विदेशी ऋण/क्रेडिट/अनुदान में से सीधे ही अदा कर दी जाती है तो वहां लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय की मिश्रित दर पर परिकल्पित आयातित माल का मूल्य रुपये में आयातकों के बैंकों द्वारा दस्तावेजों के पराक्रम सेट की पावती की तारीख से 10 दिन के भीतर भारत सरकार के लेख में जमा कराना चाहिए ।

लाइसेंस की शर्तों में यह भी प्रावधान है कि यदि निक्षेप विदेशी सम्भरकों को भुगतान की तिथि से 30 दिन के भीतर

किया जाता है तो 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज वसूल किया जाना है और यदि निक्षेप विदेशी सम्भरक को भुगतान की तिथि से 30 दिन के बाद, अदा किया जाता है तो पहले 30 दिन के लिए ब्याज की दर 9% होगी और बाकी 30 दिन से अधिक की जो अवधि है उसके लिए ब्याज की दर 15% होगी । ये दरें 15 जून, 1976 से लागू होती हैं (देखें सार्वजनिक सूचना सं. 40-आई. टी. सी. (पी एन)/76, दिनांक 16 जून, 1976) ।

2. यह देखने में आया है कि बहुत सारे मामलों में लाइसेंस शर्तों में निर्धारित समय के भीतर भारत सरकार के लेख में रुपया निक्षेप नहीं किया जा रहा है और बहुसंख्यक मामलों में देरी की अवधि बहुत लम्बी हो गई है । यह अनिवार्य है कि आयातकों और उनके बैंकों को लाइसेंस शर्तों में निहित अनुबंधों का सख्ती से पालन करना चाहिए । सरकार आयातकों द्वारा रुपया निक्षेप करने में ऐसी देरी से चिन्तित है ।

4. आवश्यकता के अनुसार इस बात के अनुपालन का सुनिश्चय करने के लिए कि रुपया निक्षेप निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, यह निश्चय किया गया है कि विदेशी सम्भरकों को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखों में रुपया निक्षेप करने की तिथि तक (दोनों दिन शामिल करके) का ब्याज 1 सितम्बर, 1983 को या उसके बाद किए जाने वाले

सभी निक्षेपों के सम्बन्ध में नीचे संकेतित अनुसार दर पर बसूल किया जाना चाहिए :—

क्रम सं.	श्रेणी	व्याज की दर
1.	ऐसे मामले जहाँ निक्षेप विदेशी सम्भरकों को भुगतान की तिथि से 30 दिन के भीतर किया जाता है।	12 प्रतिशत वार्षिक
2.	ऐसे मामले जहाँ निक्षेप विदेशी सम्भरक को भुगतान की तिथि से 30 दिन के बाद किया जाता है।	
	(क) पहले 30 दिन के लिए:—	12 प्रतिशत वार्षिक
	(ख) 30 दिन से अधिक अवधि के लिए:—	18 प्रतिशत वार्षिक

व्याज की उपयुक्त दर इस प्रकार लागू होगी :—

- (क) यदि आयातित माल और की गई सेवा की लागत 1 सितम्बर, 1983 को या उसके बाद ऋण/क्रेडिट/अनुदान में से सीधे ही अदा की जाती है।
- (ख) यदि आयातित माल या की गई सेवाओं के लिए भुगतान, 1 सितम्बर, 1983 से पहले ऋण/क्रेडिट/अनुदान में से अदा किया गया था, किन्तु 1 सितम्बर, 1983 से पहले रुपया निक्षेप आंशिक रूप में किया गया था और बाकी 1 सितम्बर, 1983 को या उसके बाद निक्षेप किया जाता है।
- (ग) यदि आयातित माल या दी गई सेवाओं के लिए भुगतान 1 सितम्बर, 1983 से पहले ऋण/क्रेडिट/अनुदान में से किया गया था किन्तु रुपया निक्षेप 1 सितम्बर, 1983 से पहले आंशिक रूप में किया गया और बाकी 1 सितम्बर, 1983 को या उसके बाद निक्षेप किया जाता है।

5. वर्तमान लाइसेंस शर्तों में इस सम्बन्ध में दिए गए प्रावधान इस सीमा तक आशोधित किए गए समझे जाएं। आयातकों को इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर वर्तमान बैंक गारन्टी के साथ अभी-अभी अधिसूचित व्याज की परिशोधित दरों से सम्बन्धित प्रावधानों के लिए संशोधन भेजने की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

पी. सी. जैन, मुख्य नियंत्रक,

(आयात एवं निर्यात)।

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 31-ITC(PN)/83

New Delhi, the 10th August, 1983

Subject : Recovery of interest from Importers in respect of imports made under the direct payment procedure against foreign loans|credits|grants—revision of rate of interest.

F. No. IPC/23/9/83.—Licensing conditions applicable to the import Licenses issued under foreign

loans|credits|grants, contain a specific clause to the effect that the rupee value of the goods imported, calculated at the composite rate of exchange applicable to the date of transaction should be deposited to the account of the Government of India within 10 days from the date of receipt of the negotiable set up documents by the importer's bankers, in cases where direct payment|commitment procedure is followed and the cost of goods imported and services are paid for directly out of the foreign loans|credits|grants.

2. The Licensing conditions also provide that interest at the rate of 9 per cent p.a. are recoverable where deposits are made within 30 days from the date of payment to the foreign suppliers and where the rupee deposits are made more than 30 days after the date of payment to the foreign supplier the interest will be 9 per cent for the first 30 days and 15 per cent for period in excess of 30 days. These rates are effective from 15th June, 1976 (vide public notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16th June, 1976).

3. It has come to notice that in very many cases rupee deposits are not being made to the account of the Government of India within the time stipulated in the licensing conditions and the delay in a number of cases is for long periods. It is imperative that importers and their bankers should strictly adhere to the instructions contained in the licensing conditions. Government are concerned at such delays in making rupee deposits by the importers.

4. As a measure to ensure compliance with the requirement that rupee deposits should be made within the prescribed period, it has been decided that interest should be recovered for the period from the date of payment to foreign suppliers to the date of rupee deposit to the Government account (both days inclusive) at the rates indicated below in respect of all deposits to be made on or after 1st September, 1983.

Sl. No.	Category	Rate of interest
1.	Cases where deposits are made within 30 days from the date of payment to the foreign suppliers.	12% per annum.
2.	Cases where deposits are made after 30 days from the date of payment to the foreign suppliers.	
	(a) For the first 30 days	12% per annum.
	(b) For period in excess 30 days.	18% per annum.

The above rates of interests will be applicable :

- (a) Where cost of goods imported and service rendered are paid for directly out of foreign loans|credits|grants on or after 1st September, 1983.
- (b) Where payment, for goods imported or services rendered, was made out of loans|credits|grants prior to 1st September, 1983, rupee deposits were made prior to 1st September, 1983, in part and the balance is deposited on or after 1st September, 1983.
- (c) Where payment, for goods imported or services rendered, was made out of loans|

credits|grants prior to 1st September, 1983 but rupee deposits were made prior to 1st September, 1983 in part and the balance is deposited on or after 1st September, 1983.

5. The provisions in this regard in the existing licensing conditions may be deemed to have been modified to this extent. Importers should also arrange to furnish amendments to existing Bank guarantees including the provisions relating to revised rates of interest now notified, within a month from the date of issue of the Public Notice.

P. C. JAIN, Chief Controller
of Imports & Exports.

